(घ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1976-77 में उस समय उपलब्ध क्षमता पर दबाव और यथा सम्भव कम समय में अधिकतम भण्डारण स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण करने विषयक एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अधीन निर्धारित की गई मुख्य-मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं :

(1) प्राइवेट पार्टियां स्वयं अपनी भूमि पर निर्माण करेंगी;

(2) गोदामों का निर्माण निगम द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाएगा;

(3) संबंधित पार्टियों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण के रूप में बैंकों द्वारा निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत सुलभ किया जाएगा, जिसका पुनर्वित्त कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा किया जाएगा और निर्माण की शेष 25 प्रतिशत लागत को संबंधित पार्टी द्वारा पूरा किया जाएगा;

(5) भारतीय खाद्य निगम इन गोदामों को 3 से 5 वर्षों की गारंटीबद्ध धारिता के आधार पर किराये पर लेगा; और

(5) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गोदाम का किराया 40 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास और शहरी क्षेत्र में स्थित गोदाम के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फीट प्रति मास की दर पर देय होगा।

(ग) जी; हां।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने यह गोदाम बांका में भण्डारण क्षमता की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किराये पर लिया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allocation to States Affected by Floods

4367. SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total amount so far sanctioned to the States affected by floods for relief measures and how much is still due to them; and

(b) whether all the affected States have utilised the funds for the purpose for which it was allotted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) A ceiling of Central Assistance of Rs. 105.56 crores has already been sanctioned to the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Meghalaya and Tripura. The request of Central Assistance for flood relief from the States of Assam, Madhya Pradesh, Sikkim, Rajasthan, Uttar Pradesh and Pondicherry and for additional assistance of Andhra Pradesh, Himachal Pradesn and Maharashtra are under processing.

(b) Since the assistance has been sanctioned recently, the utilisation report is expected after 31.3.1984.